विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम/संस्थान	मृत रोगियों की संख्या			
	1991-92	1992-93	1993-94	1994 (जुलाई तक)
महाराष्ट्र				
मानसिक अस्पताल, पुणे	164	186	133	77
—तदेव—, ठाणे	103	93	123	61
—तदेव—, नागपुर	39	31	40	20
—तदेव—, रत्नागिरि	19	13	10	4
गुजरात				
मानसिक अस्पताल, अहमदाबाद	20	16	6	2
—तदेव—, बडौदा	3	6	4	1
—तदेव—, जामनगर	5	2	3	2
—तदेव—, भुज	1	1	2	1
दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली				
आई० एच०बी०ए०एस०, दिल्ली	33	29	25	5
केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	10	9	8	—
निमहंस, बेंगलूर	6(1991)	23(1992)	10(1993)	5(जुलाई, 94 तक)
आंध्र प्रदेश				
मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, हैदराबाद	5(1991)	6(1992)	11(1993)	17(1994)
सरकारी मानसिक अस्पताल, विशाखापत्तनम	12(1991)	25(1992)	12(1993)	4(जुलाई, 94 तक)

माचिस उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी

*605. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित माचिस उद्योग को कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल की अपर्याप्त आपूर्ति या कमी के लिये जिम्मेदार कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) नरम तथा माचिस-ग्रेड को छोड़कर माचिस उद्योग के लिए सभी सच्चे माल बाजार में बिना किसी प्रतिबंध के उपलब्ध हैं। नरम काष्ठ तथा माचिस-ग्रेड का आबंटन राज्य प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। किन्तु कानपुर क्षेत्र की कुछ खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की इकाइयां सल्फर एवं पोटैशियम क्लोरेट के भंडारण की समस्या का सामना कर रही हैं।

(ख) और (ग) पोटैशियम क्लोरेट और सल्फर विस्फोटक पदार्थ होने के कारण और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की इकाइयों के पास भंडारण के लिए

पर्याप्त मात्रा में बुनियादी सुविधाएं न होने के कारण ये इकाइयां संगत अधिनियम के तहत इन पदार्थों के भंडारण के लिए लाइसेंस लेने तथा खरीद के लए अनापति प्रमाणपत्र पाने में कठिनाई का सामना कर रही हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने लाइसेंस जारी व नवीकरण करने के लिए उक्त मामले को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया है।

Sandalwood requirement by SSIs

*606. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are reviewing the requirement of sandalwood in small scale industries;

(b) whether it is a fact that there is no problem in meeting the internal requirement of sandalwood by small scale units;

(c) whether Government will make a fresh assessment of the requirement of this wood by the SSI sector; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir. However, the requirement of sandalwood for various sectors of consumers is reviewed from time to time by the respective State Governments where sandalwood is produced.

(b) to (d) The requirement of small scale units consuming sandalwood is being met satisfactorily to a great extent. As per policy the exports of sandalwood are prohibited. This has also resulted in the improved availability of sandalwood to indigenous industry. In the circumstances no urgent necessity has been felt for making any fresh assessment of the requirement of sandalwood to small scale industries.

Right to Appeal

*607. SHRI MD. SALIM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the right to appeal is inherent when a new rule for major penalty is incorporated in the rule books of Government/Public Underakings;

(b) whether it is also desirable on the principles of equity justice and fair play; and

(c) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) to (c) In the absence of mention of the specific Conduct, Discipline and appeal Rules, a precise answer is not possible. Generally speaking, right to appeal is not inherent. It is created by a statute and a rule which does not provide for such a right may not be void on that account. However, a provision for appeal is always desirable on principles of equity, justice and fair play and such a provisions is generally made.

Manufacture of Solar Cars by M/s Frazer Nash Peerless Auto Limited

*608. SHRI VIRENDRA KATARIA:
SHRI IQBAL SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Starred Question 241 given in the Rajay Sabha on 30th March, 1995 and state:

(a) by when the sloar passenger transport is likely to be manufactured and marketed by M/s Frazer Nash Peerless Auto Ltd. and what would be the approximate price of the vehicle; and

(b) what are the details of financial assistance Government have decided to extend for the manufacture of battery-operated electric vehicles and the names of the parties who have since applied for